

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157] No. 157] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2013/आषाढ़ 27, 1935

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2013/ASADHA 27, 1935

# वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2013

सं. 10/1/2012-डीबीए- I (पार्ट).— संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना

## 1. प्रस्तावना

- 1.1 औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) चुनिन्दा कार्यशील क्लस्टरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना उपलब्ध कराकर उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय क्षेत्रगत स्कीम के रूप में वर्ष 2003 में शुरू की गई थी। प्रत्येक परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 75 प्रतिशत तक की केन्द्रीय सहायता दी गई। आईआईयूएस-2003 के तहत कुल 30 परियोजनाएं मंजूर की गई थीं।
- 1.2 प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करके तथा नई परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक कठिनाइयों से बचने के प्रावधानों के जरिए योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन के परिणाम तथा कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर फरवरी, 2009 में इस योजना को पुनर्निर्मित किया गया। पुनर्निर्मित आईआईयएस के तहत 9 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।
- 1.3 इस स्कीम के लिए 10वीं योजना के दौरान 675 करोड़ रुपए तथा 11वीं योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। 2549 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत सहित 1524 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अनुदान घटक के साथ कुल 39 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

3170 GI/2013 (1)

1.4 वर्ष 2011 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा पुनर्निर्मित आईआईयूएस की प्रभावोत्पादकता और इसे 12वीं योजना अविध में जारी रखने के लिए इसका मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन करने वाली एनपीसी ने उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, औद्योगिक क्षेत्रों में वातावरण को सुधारने और परंपरागत औद्योगिक क्लस्टरों में रोजगार का सृजन करने में इस योजना को प्रभावी पाया। प्रचालनात्मक बाधाओं को दूर करने तथा परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संशोधनों के साथ इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना अविध में जारी रखने की सिफारिश की गई थी।

# उद्देश्य

संशोधित आईआईयूएस का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक वृद्धि की जरूरतों को पूरा करने तथा इसके संवर्धन, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए गुणवत्ता पूर्ण अवसंरचना उपलब्ध कराकर उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना बना रहा है।

## 3. कार्य-क्षेत्र

3.1 परियोजना को मंजूरी औद्योगिक संपदाओं/पार्कों/क्षेत्रों में अवसंरचना के उन्नयन के लिए दी जाएगी तथा ग्रीन फील्ड परियोजनाओं को, एनईआर सिहत, पिछड़े क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जा सकती है। हालांकि ग्रीनफील्ड क्लस्टर की तुलना में मौजूदा क्लस्टर में अवसंरचना के उन्नयन को वरीयता दी जाएगी। यह योजना मांग प्रेरित होगी। कार्य क्षेत्र में आवश्यकता आधारित तथा हितधारकों द्वारा वैध करार दिए गए नैदानिक अध्ययन के जिए चिहिनत संघटक शामिल होंगे। सहायता के लिए पात्र परियोजना संघटकों की विस्तृत सूची नीचे दी गई है। भारत सरकार की अन्य योजनाओं के तहत सहायता अथवा राज्य संसाधनों से निधि प्राप्त न कर सकने वाले संघटकों को प्राथमिकता दी जाएगी:

## तकनीकी अवसंरचना

सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)

अनुसंधान और विकास – उत्पाद विकास और तकनीकी प्रदर्शन सुविधा

सीईटीपी तथा अन्य पर्यावरण सुरक्षा अवसंरचना

प्रशिक्षण अवसंरचना

गुणवत्ता प्रमाणन और बैंचमार्किंग

## सामाजिक अवसंरचना

सामाजिक अवसंरचना जैसे कामकाजी महिलाओं के लिए शयनागार/हॉस्टल

## भौतिक अवसंरचना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निपटान/उपचार

जलापूर्ति

सड़कें

आंतरिक विद्युत संयंत्र (विद्युत नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार मंजूरी के लिए केवल 'आंतरिक विद्युत संयंत्र (सीपीपी)' से संबंधित परियोजनाओं पर ही विचार किया जाएगा और तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक सीपीपी के लिए ईंधन पूरी तरह प्रतिबंधित न हो)।

- 3.2 उन परियोजनाओं की नकारात्मक सूची जिन पर संशोधित आईआईयूएस के तहत विचार नहीं किया जाएगा:
- अन्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट योजनाओं जैसे चमड़ा, वस्त्र, इलैक्ट्रॉनिक्स और आईटी, खाद्य प्रसंस्करण के तहत
   तथा 'भारी उद्योग जैसे मशीन औजार, वस्त्र मशीनरी, प्रक्रिया संयंत्र मशीनरी, अर्थमूविंग मशीनरी,
   प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी तथा धातुकर्मी मशीनरी' से संबंधित विशेष रूप से शामिल परियोजनाएं/मदें।
- विस्फोटक उद्योग से संबंधित परियोजनाएं/मदें।

- भूमि की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा तथा इसके लिए केन्द्रीय अनुदान का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- 4. 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निधि का आबंटन

इस स्कीम के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 1030 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है। इसमें से 450 करोड़ रुपए 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना अविध में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयताओं के लिए होंगे। शेष 580 करोड़ रुपए का परिव्यय 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर नई परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए होगा जो प्रति राज्य दो परियोजनाओं की मंजूरी तक सीमित है। नई परियोजनाओं के लिए इस परिव्यय का न्यूनतम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में कम से कम दो परियोजनाओं के लिए चिन्हित किया जाएगा।

# 5. कार्यान्वयन एजेंसी

- 5.1 वर्ष 2011 में किए गए मूल्यांकन अध्ययनों में पाई गईं तथा योजना के कार्यान्वयन के दौरान अनुभव की गईं किमयों को दूर करके इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजना में सुधार करना महत्वपूर्ण है। इस योजना को 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना में पीपीपी मोड में विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के जिरए लागू किया गया था। तथापि इस मॉडल में गंभीर व्यवहारिक किठनाइयां सामने आईं जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब, अधिकांश परियोजनाओं के मामले में लागत में बढोतरी, परियोजना जवाबदेही की कमी तथा परिणाम की प्राप्ति में कमी आई। उद्योगों के बीच आंतरिक मतभेदों के कारण सामान्य अवसंरचना के निर्माण के लिए हितधारक उद्योगों के लिए एसपीवी के गठन हेतु एकजुट होना चुनौतीपूर्ण था। एसपीवी को अपने सदस्यों से इक्विटी प्राप्त करने, जैसा कि परियोजना में परिकल्पना की गई थी, में किठनाइयों का सामना करना पड़ा; तथा कुछ एसपीवी निधि प्राप्त करने में असफल रहीं और कुछ मामलों में राज्य सरकार और स्थानीय निकायों ने उद्योगों से प्राप्त न हो सकी निधि के बराबर का अंशदान दिया। इसके अलावा राज्य सरकारों को योजना में वैकल्पिक रूप से शामिल करने के परिणामस्वरूप परियोजना की वित्तीय, मॉनिटरिंग और सहयोगी सहायता में कमी सहित परियोजना के स्वामित्व में कमजोरी आई।
- 5.1.1 स्वीकृत 39 परियोजनाओं में से 18 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इनमें से कोई भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई; परियोजनाओं में 12 से 59 महीनों का अतिरिक्त समय लगा, परियोजनाओं को पूरा करने में लगने वाला अतिरिक्त औसत तथा मध्यम समय क्रमश: 40 महीने और 43 महीने रहा।
- 5.1.2 21 परियोजनाएं अधूरी हैं। इनमें से 15 परियोजनाएं 31.5.2010 से पूर्व मंजूर की गई थीं (जिनकी कार्यान्वयन अवधि खत्म हो गई है), जिनकी वास्तविक प्रगति 98 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है।
- 5.1.3 निर्धारित से अधिक समय लग जाने के कारण सहवर्ती लागत बढ़ गई। कुछ मामलों में परियोजनाओं का कार्य-क्षेत्र कम कर दिया गया है।
- 5.1.4 कुछ एसपीवी ने अपनी मर्जी से परियोजना घटकों को बदल दिया है तथा विशेष परियोजना घटक के लिए मंजूर अनुदान को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना दूसरे मदों के लिए दे दिया है।
- 5.1.5 ऐसी वित्तीय अनुशासनहीनता के लिए जिम्मेदारी तय करने हेतु वर्तमान प्रणाली में कोई ढांचागत तंत्र नहीं है।
- 5.2 उद्योग राज्य का विषय है। औद्योगिक अवसंरचना का संवर्धन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तदनुसार, 12वीं योजना के लिए आईआईयूएस स्कीम को संशोधित करने का प्रस्ताव है; यह प्रस्ताव है कि संशोधित आईआईयूएस, एसआईए कार्यान्वयन एजेंसी होगी, निम्नलिखित दो में से किसी एक विकल्प के अंतर्गत प्रस्ताव रखे जा सकते हैं:
- (क) किसी नए अथवा मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं/पार्कों/क्षेत्रों के निधीयन के लिए एसआईए उद्योग के साथ परामर्श करके स्थल का चयन यह सुनिश्चित करने के लिए करेगी कि उन विद्यमान औद्योगिक सम्पदाओं/पार्कों/क्षेत्रों के लिए निधियों की मांग न की जाए, जहां पर उद्योग इसे व्यवहार्य नहीं पाता है।

(ख) एसपीवी की अगुवाई वाले क्लस्टरों के माध्यम से निधीयन हेतु प्रस्ताव को एसआईए की अगुवाई वाले कार्यान्वयन मार्ग जारिए आगे बढ़ाया जाता है।

इस योजना में राज्यों की भूमिका को राज्य कार्यान्यन एजेंसी (एसआईए) को राज्य औद्योगिक विकास निगम के रूप में नामित करने के लिए पुन: परिभाषित किया गया है, ताकि परियोजना को निष्पादित किया जा सके और परियोजना लागत को बांटा जा सके। यह आशा है कि इस परिवर्तन से उन बाधाओं, जिनकी वजह से योजना की पूर्ववर्ती परियोजनाओं में विलम्ब हुआ, को दूर किया जाएगा।

5.3 एसआईए परियोजना इंटरवेंशन बनायेगी तथा परियोजना प्रगति का कार्यान्वयन तथा निगरानी करेगी। प्रत्येक आईआईयूएस परियोजना हेतु एसआईए राज्य औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) अथवा अन्य समकक्ष राज्य कंपनी हो सकती है, जो कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा चिह्नित और संस्तुत हो।

# 5.4 राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका

- 5.4.1 राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार करेगी जिसमें, किए गए नैदानिक अध्ययनों के आधार पर तकनीकी, वित्तीय तथा संस्थागत तथा कार्यान्वयन पहलुओं आदि को शामिल किया जायेगा। यह एजेंसी निम्नलिखित कार्य करेगी:-
- 5.4.2 एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी जो कि एसआईए की वार्षिक कार्य योजना की तर्ज पर होना चाहिए तथा अन्य परियोजनाओं का ब्यौरा दिया जाना चिहए जिसमें विद्यमान औद्योगिक सम्पदा अथवा पार्क वाले मामले में औद्योगिक क्षेत्र भूखण्डों का इस्तेमाल शामिल हो। एसआईए उद्योग के साथ परामर्श करके स्थल का चयन करेगी तथा इस स्कीम में औद्योगिक सम्पदाओं के निर्माण की अनुमित नहीं होगी जिसमें ऐसा करना, भूमि की उपलब्धता अथवा अन्य कारणों से, सुविधाजनक हो; बजाए इसके कि एक व्यवहार्य स्थल का चयन किया जाना चाहिए।
- 5.4.3 संकल्पना करना, सूत्रीकरण करना, वित्तीय व्यवस्था हासिल करना, अवसंरचना का कार्यान्वयन प्रचालन तथा अनुरक्षण;
- 5.4.4 नए औद्योगिक सम्पदा/पार्क के मामले में, परियोजना के लिए भूमि की अधिप्राप्ति।
- 5.4.5 वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य स्नोतों (लाभार्थी अंशदान सहित) से परियोजना के वित्तपोषण के लिए निधि जुटाना; यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त निधि की व्यवस्था करना ताकि समय की वजह से बढ़ी हुई लागत को पूरा किया जा सके।
- 5.4.6 कार्यान्वयन शुरू करने से पहले पर्यावरणीय तथा अन्य लागू गुणवत्ता मानदण्डों सहित समस्त आवश्यक सांविधिक अनुमोदन/स्वीकृतियां हासिल करना।
- 5.4.7 प्रत्येक उप-परियोजना के कार्यान्वयन से काफी पहले समय-साझा करने, प्रयोक्ता प्रभार तथा अन्य प्रचालन मानदण्डों के तौर-तरीके निर्धारित करना। इसे लागतों तथा भावी विस्तार को पूरा करने के लिए सेवा और प्रयोक्ता प्रभार एकत्रित करने हेतु शक्ति प्रदान की जायेगी। यह उपयोगिताओं तथा निर्मित की गई अवसंरचना का प्रचालन और अनुरक्षण करेगी। इस का ढांचा ऐसा बनाना होगा कि सकारात्मक राजस्व प्रवाह सहित यह आत्मनिर्भर बन सके।
- 5.4.8 ओ एण्ड एम उद्देश्यों के लिए एक अलग आरक्षित निधि खाता खोलना तथा पूंजी प्रतिस्थापन अथवा पुनर्सज्जीकरण के लिए राजस्व कम हो जाने की अवस्था में नगदी-प्रवाह प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए एक परियोजना विशिष्ट आधार पर एक समग्र आरक्षित निधि बनाना तथा उसका रखरखाव करना।
- 5.4.9 मंजूरी पत्र में उल्लिखित पात्र कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए किसी अन्य एजेंसी से अनुदान नहीं लेना।
- 5.4.10 मंजूरी पत्र में उल्लिखित संघटकों के लिए केवल भारत सरकार के अनुदान का इस्तेमाल करना, उसमें किसी प्रकार के अंतर के बारे में भारत सरकार से पूर्वानुमोदन की अपेक्षा होगी।

- 5.4.11 राज्य/केन्द्रीय सरकार की दर सूची (एसओआर) के अनुसार निर्माण कार्यों का लागत आकलन बनाना। एसआईए भारत सरकार के नियमों के अनुसार एक पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी अधिप्राप्ति प्रक्रिया के माध्यम से निर्माण कार्यों सिहत सभी प्रकार के माल, उपस्कर एवं सेवाओं अथवा किसी अन्य मद की अधिप्राप्ति करेगी।
- 5.4.12 भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना। एसआईए अनुदान के उचित इस्तेमाल के लिए एक बंध-पत्र अथवा शपथ-पत्र का निष्पादन भी करेगी, जिसमें वह इसमें उल्लिखित लक्ष्य तारीख, यदि हो, के संबंध में अनुदान शर्तों का अनुपालन करने के लिए वचन देगी। यह अनुदानों को अन्यत्र अंतरित नहीं करेगी तथा स्कीम अथवा संबंधित कार्य को दूसरे संस्था/संस्थाओं अथवा संगठन को नहीं सौंपेगी तथा अनुमोदन पत्र में विनिर्दिष्ट किसी अन्य शर्त का भी पालन करेगी और शर्तों के अनुपालन करने में विफल हो जाने की अवस्था में अथवा बंध-पत्र/शपथ-पत्र का उल्लंघन करने पर यह सम्पूर्ण अनुदान राशि को 10 प्रतिशत ब्याज की दर सहित भारत के राष्ट्रपति को लौटाने के लिए जिम्मेदार होगी।
- 5.4.13 यह किसी स्वतंत्र लेखा परीक्षक से भारत सरकार की संतुष्टि स्तर तक अपने लेखाओं की लेखा परीक्षा कराएगी तथा लेखा परीक्षा में सहयोग करेगी।

# 5.5 कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं?

- 5.5.1 एसआईडीसी जैसी राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियां संशोधित आईआईयूएस के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु आवेदन कर सकती हैं।
- 5.5.2 **पात्रता मानदण्ड:** एसआईए को प्रस्तावित किस्म की परियोजना कार्यनिष्पादन के संबंध में पर्याप्त विगत अनुभव होना चाहिए; एसआईए का पिछला अनुभव इस स्कीम के अंतर्गत एजेंसी को परियोजना का कार्य सौंपने के लिए एक बड़ा मानदण्ड होगा।

## 5.6 परियोजना प्रस्ताव तैयार करना

- 5.6.1 परियोजना प्रस्ताव की नींव रखने के लिए चिहिनत औद्योगिक सम्पदाओं/क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण तथा अध्ययन करने तथा विश्वसनीय आंकड़े तैयार करने के बाद परियोजना प्रस्ताव भलीभांति संकल्पित और सावधानीपूर्वक तैयार किया गया होगा। उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता पर असर डालने वाले अवसंरचना के महत्वपूर्ण अंतरालों का प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उत्पादकता तथा रोजगार में प्रत्याशित विस्तार जैसी मापने योग्य परिणामों को परियोजना प्रस्ताव में समावेशित किया जाना चाहिए, जो परियोजनाओं की मंजूरी हेतु मुख्य मानदण्डों में से भी एक होना चाहिए। प्रस्ताव में उन संकल्पित परिणामों तथा संकेतकों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिन पर परियोजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसे प्रयोक्ता प्रभार/शुल्क आदि लगाकर सतत आधार पर निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित अवसंरचना के प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए तंत्र के संबंध में भी बताना चाहिए।
- 5.6.2 विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) में निर्माण का वास्तविक लागत अनुमान, तकनीकी विनिर्देशन तथा संयंत्र तथा मशीनरी के लागत अनुमान, खण्ड संबंधी नक्शे तथा पुराने अनुभव युक्त भवन निर्माण योजना से युक्त विस्तृत मास्टर प्लान, बेंचमार्क से युक्त वित्तीय अनुमान (प्रयोक्ता प्रभार, क्षमता इस्तेमाल) वित्तीय सूचकांकों (डीएससीआर आईआरआर आदि) से युक्त अनुमानित वित्तीय विवरण (पी एवं एल तुलन पत्र, नगदी प्रवाह आदि) को शामिल किया जाना चाहिए। इस जीएफआर से प्रत्येक इन्टरवेन्शन का प्रत्याशित परिणाम स्पष्टत: स्थापित हो जायेगा, जो पीईआरटी चार्ट के रूप में फर्म के कार्यान्वयन कार्यक्रम से युक्त मापने योग्य होना चाहिए जिसमें कार्यकलाप/घटक-वार समय सीमाएं दर्शाई गई हों।
- 5.6.3 प्रत्येक संघटक के लिए, डीएफआर में प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय का व्यापक विश्लेषण तथा इसके लिए वित्त संबंधी कार्यनीति शामिल होगी।
- 5.6.4 निर्मित अवसंरचना की निरन्तरता पात्र परियोजना संघटकों के मूल्यांकन के लिए एक मुख्य मूल्यांकन मानदण्ड होगा।
- 5.6.5 डीएफआर में जल संरक्षण के लिए अवसंरचना निर्माण जैसे कि बारिश के पानी का भण्डारण तथा उचित शोधन के बाद संभावित जल पुनर्प्रयोग की भी संकल्पना होनी चाहिए। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के पास उपलब्ध

वर्तमान प्रौद्योगिक समाधानों तथा डीएसटी वेबसाइट में प्रौद्योगिकी पोर्टल/प्रौद्योगिकी कम्पोडियम में सूचीबद्ध सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का सदुपयोग करने का भी प्रयास किया जायेगा। प्रस्ताव में शैक्षिक-उद्योग संपर्कों से लाभ प्राप्त करने के लिए किसी शैक्षिक/अनुसंधान संस्था को शामिल अथवा उसकी पहचान भी करनी चाहिए।

5.6.6 एसआईए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने तथा अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन में सहायता हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) की सेवाओं को नियुक्त /इस्तेमाल कर सकती है।

5.6.7 लाभार्थी अंशदान वाली परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

# 6. अनुमोदन प्रक्रिया

- 6.1 दो स्तरीय अनुमोदन प्रणाली अपनाई जाएगी:
  - क. परियोजना का 'सैद्धांतिक' अनुमोदन -डीएफआर के आधार पर
  - ख. 'अंतिम अनुमोदन'- कुछ पूर्व-अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने के आधार पर
- 6.2 डीएफआर का मूल्यांकन एसआईए की वचनबद्धता, परियोजना की अवस्थिति, भूमि ब्यौरे, वित्तीय मजबूती, प्रस्तावित परियोजना ब्यौरे तथा कार्यान्वयन की तत्परता पर आधारित होगा। 'सिद्धांत:' अनुमोदन शीर्ष समिति द्वारा दिया जाएगा जो जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए मान्य होगा। शीर्ष समिति का संयोजन सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा **अनुबंध-क** के अनुसार किया जाएगा।
- 6.3 एमआईआईयूएस की अधिसूचना जारी होने के बाद परियोजना प्रस्ताव के लिए अनुरोध कम से कम दो समाचार-पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। विज्ञापन की तारीख से विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) को मिलाकर परियोजना प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त समयसीमा दी जाएगी।
- 6.3 परियोजना का अंतिम अनुमोदन

इस परियोजना को निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने के बाद शीर्ष समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

- 6.3.1 भूमि का वास्तविक कब्जा
  - भूमि की खरीद की जानी चाहिए और एसआईए के नाम पंजीकृत/हस्तांतरित की जानी चाहिए। परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का वास्तविक कब्जा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 6.3.2 वित्तीय मूल्यांकन/बंदी
  - इसका आबंटन एसआईए के बजट में किया जाना चाहिए।
  - सभी हितधारकों से ब्यौरा/वचनबद्धता/अंशदान का सबूत
  - एफआई के अंशदान के लिए अंतिम स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाना चाहिए।
  - ऋण वित्तपोषण के मामले में डीआईपीपी के विचारार्थ बैंक से मूल्यांकन टिप्पणी। स्व:वित्तपोषण के मामले में राज्य/केंद्रीय वित्त एजेंसी द्वारा मूल्यांकन टिप्पणी।
- 6.3.3 विस्तृत डीपीआर
  - -लागत अनुमानों सहित मशीनरियों एवं उपकरणों का विस्तृत विवरण।
  - -योजना दिशानिर्देशों के लिए तकनीकी अनुपालन।
  - -कंपनी अनुपालन अनुसूची।
  - -परियोजना में अपेक्षित सभी मंजूरियों की प्रतियां।

## 7 निधि पैटर्न

7.1 केंद्र सरकार 50 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक परियोजना लागत का 50% तक अंशदान करेगी। शेष अंशदान एसआईए, लाभार्थी उद्योगों और वित्तीय संस्थानों से ऋण से होगा। एसआईए का

- न्यूनतम अंशदान परियोजना लागत का 25% होगा। पूर्वीत्तर राज्यों के मामले में केंद्रीय अनुदान तथा एसआईए का न्यूनतम अंशदान क्रमश: 80% तथा 10% होगा।
- 10% के न्यूनतम लाभार्थी उद्योग अंशदान वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी 7.2 प्रकार 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में बेहतर उपलब्धियों वाले राज्यों को नई परियोजनाओं की स्वीकृत में प्राथमिकता दी जाएगी।
  - भौतिक अवसंरचना के लिए केंद्रीय अनुदान 12.5 करोड़ रुपए के अध्यधीन केंद्रीय अनुदान का 25% तक होगा। परियोजना के सीईपीटी घटक पर 15 करोड़ रुपए/सीईपीटी (अधिकतम 1.50 करोड़ रुपए/ एमएलडी) की सीमित सहायता के अध्यधीन तथा 20 करोड़ रुपए/सीईपीटी (4.50 करोड़ रुपए/ एमएलडी) तक की जेडएलडी ट्रीटमेंट (जीरो डिस्चार्ज) अधिकतम सहायता के लिए विचार किया जाएगा।
- 7.4 केंद्रीय अनुदान वित्तपोषण केवल टिकाऊ परिसंपत्तियों के सुजन एवं उत्पादकता विस्तार से संबंधित क्रियाकलापों के लिए होगा और इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसी आवर्ती व्यय का वित्तपोषण नहीं किया जाएगा।
- केंद्रीय सहायता एक बार की अनुदान सहायता (इक्विटी नहीं) होगी और अन्य हितधारकों का अंशदान 7.5 नगद रूप में होना चाहिए तथा भूमि/मौजदा भवन की लागत के रूप में नहीं होनी चाहिए।
- निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासनिक लागत के लिए व्यय केंद्रीय अनुदान का 5% हो ताकि 7.6 लिखित एवं दृश्य इनपूट्स के साथ फील्ड दौरे करने तथा एक मजबूत वेब युक्त रिपोर्टिंग तंत्र का निर्माण करने के लिए आउटसोर्सिंग और/अथवा परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए) लगाने के माध्यम से डीआईपीपी में सहयोगी मूल्यांकन की उचित प्रणाली स्थापित की जा सके। केंद्रीय अनुदान के 3% तक जो कुल मिलाकर आईआईयुएस परियोजनाओं के लिए स्वीकृत केंद्रीय अनुदान है, को आईआईयुएस बजट से पूरा किया जाएगा और आईआईयूएस परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित 50% की केंद्रीय सहायता को कम किए बिना परियोजनाओं के मूल्यांकन, निगरानी तथा मूल्य निर्धारण के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा उपयोग किया जाएगा। एसआईए को प्रारंभिक एवं पूर्व-क्रियाशील खर्चीं, परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सहित उनके प्रशासनिक खर्चों पर केंद्रीय अनुदान का 2% तक वहन करने की अनुमति होगी। एसआईए निर्धारित सीमा के अतिरिक्त सभी खर्चों को उनके अपने संसाधनों से पूरा करेगा।
- परियोजना लागत के डाउनवर्ड संशोधन के मामले में केंद्र सरकार अनुदान को समानुपाती रूप से कम 7.7 किया जाएगा।
- एसआईए द्वारा केंद्रीय अनुदान पर अर्जित ब्याज को केंद्रीय अनुदान के भाग के रूप में समझा जाए। 7.8
- भूमि एवं भूमि विकास लागत, कार्यशील पूंजी और विविध खर्चों को परियोजना लागत से बाहर रखा 7.9 जाएगा।
- समय तथा लागत बढ़ने के कारण परियोजना लागत में उच्च खर्च राज्य कार्यान्वयन एजेंसी अथवा अन्य हितधारकों द्वारा वहन किया जाए।
- पूरा होने की समय-सीमा 8.

परियोजना के लिए कार्यान्वयन अनुसूची परियोजना के आकार एवं प्रकृति के आधार पर होगी। सामान्य रूप में परियोजना के अंतिम अनुमोदन के बाद 2-3 वर्षों की समयावधि पर्याप्त होगी और 'शीर्ष समिति' द्वारा अनुमोदित अनुसार अनुमोदित समय-सीमा का कड़ाई से पालन होना चाहिए।

9. राज्य सरकार की भूमिका राज्य सरकार की भूमिका में योजना कार्यान्वयन को केंद्रीय रूप से सुकर बनाने की परिकल्पना की गई है। डीआईपीपी द्वारा प्राप्त सभी परियोजना प्रस्ताव एसआईए और राज्य उद्योग विभाग अथवा किसी अन्य संबंधित विभाग के संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। योजना में उन प्रस्तावों पर महत्व दिया जाएगा जिनका फोकस बैकवर्ड क्षेत्रों के विकास पर होगा और जहां मौजूदा क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं अधिक्रमण करने में असमर्थ हो गई हैं। पैरा 5.4.12 के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसमें सरकार की भूमिका परियोजनाओं की निगरानी के लिए स्पष्ट रूप से लिखित होगी और विनिर्दिष्ट एसआईए को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

## 10. निधि जारी करना

- 10.1 भारत सरकार अपना अनुदान 3 किस्तों में जारी करेगी।
- 10.2 अनुमोदित अनुदान के 30% के समतुल्य केंद्रीय अनुदान की प्रथम किस्त यह सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाएगी कि एसआईए और उद्योग ने त्रिपक्षीय करार के आधार पर खोले गए ट्रस्ट एवं रिटेन्शन लेखा (टीआरए) में उनके अंशदान का 30% पहले ही डाल दिया है।
- 10.3 अनुमोदित अनुदान के 40% के समतुल्य केंद्रीय अनुदान की दूसरी किस्त परियोजना लागत के 22.5% का उपयोग करने और यह सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाएगी कि एसआईए ने अन्य हितधारकों सिहत बैंक खाते में उनके अनुमोदित अनुदान का 70% पहले ही डाल दिया है।
- 10.4 अनुमोदित अनुदान के 30% के समतुल्य केंद्रीय अनुदान की तीसरी किस्त भारत सरकार के अनुदान की प्रथम किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति और परियोजना लागत के 52.5% का उपयोग करने तथा यह सुनिश्चित करने के बाद जारी की जाएगी कि एसआईए ने अन्य हितधारकों सहित बैंक खाते में उनका समग्र अनुमोदित अंशदान पहले ही डाल दिया है।

## 11. निगरानी तथा समीक्षा

- 11.1 एसआईए का शासी बोर्ड परियोजना की प्रक्रिया की निगरानी कम से कम तिमाही में एक बार करे और एसआईए के सीईओ के हस्ताक्षर से निर्धारित प्रपत्र में डीआईपीपी को तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) भेजें।
- 11.2 फील्ड दौरे करने तथा एक मजबूत वेब युक्त रिपोर्टिंग तंत्र का निर्माण करने के लिए आउटसोर्सिंग और/अथवा परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए) लगाने के माध्यम से डीआईपीपी में सहयोगी मूल्यांकन की उचित प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- 11.3 डीआईपीपी एसआईए के शासी बोर्ड के लिए अपने नामिती नियुक्त करेगा।
- 11.4 शीर्ष समिति परियोजनाओं की प्रगति की वार्षिक रूप से निगरानी करेगी।

# 12. परियोजना प्रबंधन एजेंसी

- 12.1 डीआईपीपी एक स्वतंत्र एजेंसी नामत: परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) लगाएगा जो अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना के तकनीकी तथा वित्तीय मूल्यांकन दोनों का कार्य करेगी। पीएमए, एसआईए द्वारा विशेषकर तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय असमर्थता तथा संलग्न संसाधनों का इष्टतम उपयोग के संबंध में प्रस्तुत डीएफआर एवं डीपीआर का मूल्यांकन करेगी। नियुक्त पीएमए की लागत प्रशासनिक खर्चों के तहत परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा निगरानी के लिए अलग से निर्धारित निधि से पूरा की जाएगी।
- 12.2 पीएमए के कार्य एवं जिम्मेदारियां इस प्रकार होंगी:-
  - एसआईए द्वारा सिद्धांतत: अनुमोदन के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग को प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन।
  - अंतिम अनुमोदन के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन।
- 12.3 पीएमए इस परियोजना में कोई भी परामर्शी कार्य नहीं करेगा।

# 13. परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी)

एसएआई आवश्यकता के आधार पर एक पीएमसी की नियुक्ति कर सकता है पीएमसी की नियुक्ति एसएआई के लिए वैकल्पिक होगी तथा इसकी आवश्यकता अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होगी।

14. माल एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति

- 14.1 माल उपस्कर एवं सेवाओं संबंधी सभी अधिप्राप्ति एक खुले, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से होगी। परियोजना को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध में उपयुक्त कार्य-निष्पादन गारंटी दी जानी चाहिए।
- 14.2 अधिप्राप्ति नीति का सरकारी सामान्य वित्त नियमों (जीएफआर) के अनुसार होना आवश्यक है।

## 15. परिसम्पत्तियां

- 15.1 एसआईए द्वारा सरकारी सहायता से प्राप्त/सृजित परिसंपत्तियों का जिस प्रयोजन हेतु निधियां जारी की गई हैं उनके अलावा, निपटान, ऋण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- 15.2 जिन्हें समग्र रूप से अथवा मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधि से प्राप्त की गईं स्थायी एवं अर्ध-स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्टर का रखरखाव फार्म जीएफआर 19 में किया जाना चाहिए।
- 15.3 एसआईए ओ एवं एम लागत की पूर्ण वसूली तथा परियोजना को सतत बनाए रखने के लिए इसके द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं एवं सेवाओं हेतु उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभार निर्धारित करेगी।
- 15.4 किसी भी समय एसआईए के विघटन अथवा परियोजना के निरस्तीकरण के मामले में, सभी परिसंपत्तियां एवं अप्रयुक्त अनुदान भारत सरकार के अधिकृत होगी।

# 16. केंद्रीय अनुदान वापस मांगना

परिकल्पित गुणवत्ता को पूरा न करने, अथवा परियोजना का आंशिक/अपूर्ण कार्यान्वयन सहित अनुदान के असंतोषजनक उपयोग के मामले में लागू दंडस्वरूप ब्याज के साथ केंद्रीय अनुदान में कमी/वापस मांगने का अधिकार शीर्ष समिति के पास कायम रहेगा।

<u>अनुबंध-क</u>

# शीर्ष समिति का गठन

# अध्यक्ष

सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

## सदस्य

- 1. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- 2. आर्थिक सलाहकार, औ.नी.एवं सं.वि.
- 3. \* प्रतिनिधि, योजना आयोग
- 4. \* प्रतिनिधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
- 5. \* प्रतिनिधि, वाणिज्य विभाग
- 6. \* प्रतिनिधि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
- 7. \*\* सचिव, उद्योग संबंधित राज्य सरकार से
- 8. \*\* एसआईए एवं एसपीवी/उद्योग संघ का सीईओ
- 9. संबंधित वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि
- 10. एसआईए की शासी निकाय में भारत सरकार द्वारा नामित व्यक्ति।

# सदस्य सचिव

संयुक्त सचिव, औ.नी.एवं.सं.वि.

विशेष रूप से आमंत्रित: पीएमए

# पीएमसी

- \*प्रतिनिधि संयुक्त सचिव के रैंक के नीचे के नहीं होने चाहिएं
- \*\* सचिव/सीईओ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। किसी भी प्रतिनिधि को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

# MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Industrial Policy and Promotion) NOTIFICATION

No. 10/1/2012-DBA-1(Part).—Modified Industrial Infrastructure Upgradation Scheme

### 1. Introduction

- 1.1 Industrial Infrastructure Upgradation Scheme (IIUS) was launched in 2003 as a Central Sector Scheme to enhance competitiveness of industry by providing quality infrastructure through public private partnership in selected functional clusters. Central assistance upto 75% of the project cost subject to a ceiling of Rs. 50 crore was given for each project. Total 30 projects were sanctioned under IIUS -2003.
- 1.2 Based on the outcome of an independent evaluation and experiences gained during the implementation, the Scheme was recast in February, 2009 to make it more effective through increased focus on technological upgradation and provisions to avoid initial teething problems for new projects. 9 projects have been sanctioned under Recast IIUS 2009.
- 1.3 The Scheme had an allocation of Rs. 675 crore during the 10th Plan and Rs. 1050 crore for the 11<sup>th</sup> Plan. A total of 39 projects have been sanctioned with a total project cost of Rs. 2549 crore with central grant component of Rs. 1524 crore.
- 1.4 In 2011, the Recast IIUS was evaluated for its effectiveness and continuation in the 12<sup>th</sup> plan period by the National Productivity Council (NPC). The NPC which conducted the evaluation, found the Scheme to be effective in enhancement of competitiveness of industry, improvement of environment in industrial areas and employment generation in the traditional industry clusters. It was recommended to continue the Scheme in the 12<sup>th</sup>Five Year Plan period with suitable modifications, to overcome operational hurdles and ensure timely completion of projects.

## 2. Objective

The key objective of the Modified IIUS continues to be to enhance competitiveness of industry by providing quality infrastructure to catalyse and promote industrial growth, employment generation and technology upgradation.

### 3. Scope

3.1 Projects would be sanctioned to upgrade infrastructure in Industrial Estates/Parks/Areas and greenfield projects could be supported in backward areas, including NER. However, PRIORITY would be given to upgrade infrastructure in existing cluster over Greenfield cluster. The scheme will be demand driven. The scope will cover components that are need based and identified through a diagnostic study which is validated by stakeholders. An illustrative list of project components eligible for assistance is given below. Priority would be for those components that cannot be assisted under other available schemes of Government of India or funded from state resources:

Technical Infrastructure
Common Facility Centres (CFCs)
Research and Development - Product Development and Technical Demonstration Facility
CETP and other environment protection infrastructure
Training Infrastructure
Quality Certification and Benchmarking

Social Infrastructure
Social infrastructure like dormitories/hostels for working women
Physical Infrastructure
Solid Waste Management disposal/treatment
Water Supply
Roads

Captive Power Plant (the project relating to 'Captive Power Plant (CPP)' will only be considered for sanction as per the provisions of Electricity Rules 2005 and will not be considered unless fuel for the CPP is fully tied up).

- 3.2 Negative List of Projects that will not be considered under MIIUS:
- Projects/Items covered under specifically under other Sector Specific Schemes like Leather, Textiles, Electronics & IT, Food Processing and relating to 'Heavy Industry such as Machine Tools, Textile Machinery, Process Plant Machinery, Earth Moving Machinery, Plastic Processing Machinery and Metallurgical Machinery'.
- Projects/Items relating to Explosives Industry.
- Cost of Land shall not be included in the project cost and central grant shall not be used for this purpose.
- 4. Fund allocation for the 12<sup>th</sup> Five Year Plan

An outlay of Rs.1030 crore has been allocated for the Scheme in the 12<sup>th</sup> Five Year Plan. Of this, Rs. 450 crore would be towards the committed expenditure for the projects sanctioned in the 10<sup>th</sup> and 11<sup>th</sup> Five Year Plan periods. The balance outlay of Rs. 580 crore would be utilized for sanctioning new projects on first come first serve basis, limiting sanction of two projects per state. A minimum of 10% of this outlay for new projects will be earmarked for at least 2 projects in the NER and Sikkim.

### 5. Implementation Agency

- 5.1 It is important to improvise the Scheme to make it more effective by addressing the shortcomings found in the evaluation study undertaken in 2011 as well as those experienced during implementation of the Scheme. The Scheme was implemented through Special Purpose Vehicles (SPVs) in the PPP mode in the 10<sup>th</sup> and 11<sup>th</sup> Plan. However, this model has faced serious practical difficulties which has led to enormous delay in implementation, cost escalation in case of majority of the projects, lack of project accountability and shortfalls in achievement of outcome. It was challenging for stakeholder industries to unite to form a SPV for creating a common infrastructure due to internal conflict among industries. The SPVs faced difficulties in raising equity from its members as envisaged in the project; and some SPVs defaulted in raising funds and in some cases, state government and local bodies contributed funds to the extent of failed contributions from the Industries. Further, optional involvement of the State Governments in the scheme led to weak ownership of the project with reduced financial, monitoring and mentoring support to the project.
- 5.1.1 Out of the 39 sanctioned projects, 18 Projects have been completed. None of these projects was completed on time; the projects suffered a time over run of 12 to 59 months, the average and median time over run being 40 months and 43 months respectively.
- 5.1.2 21 projects are incomplete. Of these 15 projects were sanctioned prior to 31.5.2010 (for which the implementation period is over), with physical progress ranging between 98 % and 5 %.
- 5.1.3 On account of time over run, concomitant cost over runs have occurred. In some cases the scope of the projects has been reduced.
- 5.1.4 Some SPVs have changed project components at will and diverted grant sanctioned for specific project component to other items, without the approval of the sanctioning authority.
- 5.1.5 There is no structured mechanism in the present system to ensure accountability for such financial indiscipline.
- 5.2 Industry is a State subject. Promotion of the industrial infrastructure is the responsibility of the State Government. Accordingly, it is proposed to modify the IIUS Scheme for the XIIth Plan; it is proposed that under the revised IIUS, SIA would be the implementing agency, the proposals could be taken up under either of the following two options:
  - (a) For funding of new or existing Industrial Estates/Parks/Areas, SIA would chose the site in consultation with the industry to assure that funds are not sought for Industrial Estates/Parks/Areas in place where industry does not find it viable.
  - (b) For funding through SPV-led Clusters, the proposal is routed through the SIA-led implementation route. The role of States in the Scheme has been re-defined for nominating the State Implementation Agency (SIA) such as State Industrial Development Corporations for execution of the project and sharing the project cost. It is expected that with this change, bottlenecks which delayed the projects in earlier versions of scheme would be overcome.
- 5.3 SIA will formulate the project interventions as well as implement and monitor the progress of the project. The SIA for each IIUS project could be the State Industrial Development Corporation (SIDC) or any equivalent state entity as identified and recommended by the respective State Government.

## 5.4 Role of the State Implementing Agency

5.4.1 The State Implementing Agency (SIA) will prepare Detailed Feasibility Reports (DFR) covering technical, financial, and institutional and implementation aspects, based on diagnostic studies undertaken. The agency would:

- 5.4.2 Submit a project proposal that should be in line with SIA's Annual Action Plan and should give details of other projects including utilization of industrial area plots in case of an existing industrial estate or park. SIA shall select the site in consultation with the industry and the scheme shall not permit creating industrial estates wherein it shall be convenient to do so due to availability of land or other reasons; rather a viable site should be selected.
- 5.4.3 Conceptualize, formulate, achieve financial closure, implement, operate and maintain the infrastructure;
- 5.4.4 Procure the land for the project, in case of a new industrial estate/park.
- 5.4.5 Mobilize funds from financial institutions and other sources (including beneficiary contributions) to finance the project; arrange additional funds, if required, to meet time and cost overruns.
- 5.4.6 Obtain all necessary statutory approvals/clearances including environmental and quality standards as applicable before implementation.
- 5.4.7 Decide on methodology of time-sharing, user charges and other operating parameters well in advance before implementation of each sub-project. It would be empowered to collect service and user charges to recover costs and future expansion. It will operate and maintain the utilities and infrastructure created. It has to be so structured as to be self-sustaining with a positive revenue stream.
- 5.4.8 Set up a separate Reserve Fund Account for O&M purposes and to create and maintain a reserve corpus on a project specific basis to be utilized for cash-flow management in case of revenue shortfalls for capital replacement or refurbishments.
- 5.4.9 Not obtain grant from any other agency for implementing the eligible activities mentioned in the sanction letter.
- 5.4.10 Utilize GOI grant only for the components mentioned in the sanctioned letter; any deviation from there would require prior approval of Government of India in writing.
- 5.4.11 Estimate cost for works as per the Schedule of Rates (SOR) of the State/Central Government. The SIA shall undertake all procurement of goods, equipment & services or any other item including works through a transparent and competitive procurement process as per Government of India Rules.
- 5.4.12 Sign an MOU with Government of India and the State Government concerned. The SIA shall also execute a bond/undertaking for proper utilization of grant wherein, it shall undertake to abide by the conditions of the grant by the target dates, if any, specified therein; It shall not divert the grants and entrust execution of the scheme or work concerned to another institution(s) or organization, and shall also abide by any other condition specified in the approval letter and in the event of failing to comply with the conditions or committing breach of the bond/undertaking it shall be liable to refund to the President of India the entire amount of the grant with interest @ 10% per annum thereon.
- 5.4.13 Shall undertake audit of its accounts to the satisfaction of GOI, independent auditor and cooperate in the audit.

### 5.5. Who can apply?

- 5.5.1 State Implementation Agencies such as SIDCs can apply for funding under the Modified IIUS.
- 5.5.2 Eligibility Criterion: SIAs should have sufficient past experiences relating to execution of nature of projects proposed to be undertaken; past experience of SIA will be one of the major criteria for entrusting a project to the agency under the scheme.

### 5.6 Formulation of the Project Proposal

- 5.6.1 The project proposal shall be well conceptualised and formulated meticulously after conducting detailed survey and study of the identified industrial estates/areas and generating credible data for laying the foundation of the project proposal. The critical gaps in the infrastructure impinging upon the competitiveness of the industry should be clearly brought out in the proposal. Measurable outcomes such as expected enhancement in productivity and employment should be incorporated into the project proposal which would also be one of the main criteria for sanctioning the projects. The proposal must spell out outcomes envisaged and the indicators that would be positively impacted by the project. It should also suggest the mechanism for operation and maintenance of the infrastructure proposed to be created on sustained basis by levying user charges/fee etc.
- 5.6.2 The Detailed Feasibility Report (DFR) should include realistic cost estimate of construction, technical specifications and cost estimates for plant and machinery, detailed master plan along with sectional drawings and building plan with legends, financial assumptions (user charge, capacity utilization) with benchmarks, projected financial statements (P&L, Balance Sheet, Cash Flow, etc) with financial indicators(DSCR, IRR, etc), This DFR would clearly establish the expected outcome of each of the interventions, which should be measurable along with a firm implementation schedule in the form of a PERT chart showing activity/component wise timelines.
- 5.6.3 For each component, the DFR shall include detailed analysis of Operation and Maintenance Expenditure and the financing strategy for the same.
- 5.6.4 Sustainability of infrastructure created will be a key evaluation parameter for assessing eligible project components.
- 5.6.5 DFR should also visualise creation of infrastructure for water conservation, such as rainwater harvesting and possible recycle and reuse of water after proper treatment. Efforts would also be made to tap the existing technology

solutions available with national laboratories as well as other public funded R&D efforts enlisted in the Technology Portal/Technology Compendium in DST website. The Proposal may also include or identify an academic/research institution for getting benefits of academic-industry linkages.

- 5.6.6 The SIA may appoint and use services of a Project Management Consultant (PMC) to support SIA for preparation of project proposal as well as assistance in the execution for the approved projects.
- 5.6.7 Projects with beneficiary contribution shall be encouraged.

### 6 Approval Process

- 6.1 Two Stage approval system will be adopted:
  - a. 'In-Principle' approval of the Project Based on DFR
  - b. 'Final Approval' Based on fulfillment of certain pre-requisite criterion.
- 6.2 The DFR will be appraised based on parameters such as commitment of the SIA, location of the project, land details, financial strength, proposed project details and readiness for implementation. 'In-principle' approval will be given by an Apex Committee which will be valid for a period of six months from the date of issue. The composition of the Apex Committee chaired by the Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion will be as per Annexure-A.
- 6.3 After the issue of notification of the MIIUS, request for project proposal will be invited through advertisements in at least two newspapers. Suitable timeframe would be given for submission of project proposal inclusive of a detailed feasibility report (DFR) from the date of advertisement.

## 6.3 Final Approval of the Project

The project will be accorded final approval by the Apex Committee after achieving the following milestones:

- 6.3.1 Physical possession of the land
  - Land should be procured and registered/ transferred in the name of the SIA; Physical possession of the land required for the project is to be ensured.
- 6.3.2 Financial Appraisal / Closure
  - Allocation for the same should have been made in the SIA's budget
  - Details/Commitment/Proof of Contributions from all the stakeholders
  - Final Sanction letter should be provided for FIs contribution
  - Appraisal Note from the Bank for DIPPs consideration, in case of debt financing. In case of self financing, appraisal note by the state/central financial agency
- 6.3.3 Detailed DPR
  - Detailed specifications of machineries and equipments with cost estimates
  - Technical compliance to scheme guidelines
  - Firm implementation schedule
  - Copies of all the Clearances required in the project

### 7. Funding Pattern

- 7.1 The central government will contribute upto 50% each of the project cost subject to a ceiling of Rs.50 Crore. The remaining contribution will be from the SIA, beneficiary industries and loan from financial institutions. The minimum contribution of the SIA will be 25% of the project cost. In case of North Eastern States, the central grant and the minimum contribution of the SIA will be 80% and 10% respectively.
- 7.2 Projects with minimum beneficiary industry contribution of 10% shall be given priority. Similarly States with a better track record of implementing IIUS in 10<sup>th</sup> & 11<sup>th</sup> FYPs will be given priority in sanction of new projects.
- 7.3 Central grant for Physical infrastructure will be upto 25% of the central grant subject to a ceiling to Rs.12.5 crore. 'CETP' component of the project would be considered subject to ceiling of assistance upto Rs. 15 crore/CETP (maximum Rs. 1.50 crore/MLD) and for ZLD treatment (Zero Discharge) maximum assistance upto Rs. 20 crore/CETP (Rs. 4.50 crore/MLD).
- 7.4 Central government funding will be confined only to creation of durable assets and activities relating to productivity enhancement and no recurring expenditure will be funded by Central Government under the scheme.
- 7.5 The central assistance will be a onetime grant-in-aid (not equity) and the contributions of other stakeholders must be in the form of cash and not in kind like the cost of land/existing building.
- 7.6 For strengthening the monitoring mechanism, expenditure towards administrative cost is raised to 5% of central grant so that appropriate system of concurrent evaluation can be set up in the DIPP through outsourcing and/ or engaging a Project Monitoring Agency (PMA) to undertake field visits and build up a strong web enabled reporting mechanism, with documentary and visual inputs. Upto 3% of central grant which is over and above the central grant sanctioned to IIUS projects would be met from IIUS Budget and will be used by the Department of Industrial Policy &

Promotion for appraisal, monitoring and evaluation of the projects without reducing central assistance of 50% proposed to IIUS projects. The SIAs would be allowed to incur upto 2% of the central grant on their administrative expenses including preliminary and preoperative expenses, hiring of Project Management Consultants (PMCs). The SIAs will meet all expenses beyond the prescribed limit from their own resources.

- 7.7 In case of downward revision of project cost, the central government grant would be reduced proportionately.
- 7.8 Interest earned on central grant by the SIA to be treated as a part of the central grant.
- 7.9 Land and Land development cost, working capital and contingencies shall be excluded from the project cost.
- 7.10 Higher expenditure in the project cost due to time and cost-overruns have to be borne by the State Implementing Agency or other stakeholders.

### 8. **Timeline for completion:**

Implementation Schedule for the projects would be on the basis of size and nature of the project. In general, a time period of 2-3 years after the final approval to the project, would be considered adequate and approved timelines as approved by the 'Apex Committee' shall be adhered to strictly.

### 9. Role of the State Government

The role of the State Government is envisaged to be central to the facilitation of the scheme implementation. All project proposals received by DIPP have to be approved by the respective Board of SIA and the State Industries Department or any other concerned Department. The Scheme will give weightage to those proposals which could focus on development of backward areas and where the existing sector specific schemes have been unable to make inroads. As per paragraph 5.4.12 an agreement will be signed wherein role of the Government would be clearly spelt out for monitoring of projects and provide financial support to the designated SIA.

### 10. Release of Funds

- 10.1 The Government of India will release its grant in 3 installments.
- 10.2 The first installment of the matching central grant of 30% of the approved grant will be released after ensuring that SIA and the industry have already brought in 30% of their contribution in the Trust & Retention Account (TRA), opened on the basis of a tripartite agreement.
- 10.3 The second installment of matching central grant of 40%\_of the approved grant will be released after utilization of 22.5% of the project cost and ensuring that SIA along with other stakeholders have already brought in the 70% of their approved contribution in the Bank Account.
- 10.4 The 3<sup>rd</sup> installment of matching central grant of 30%\_of the approved grant will be released after receipt of utilization certificate for the 1<sup>st</sup> installment of GOI's grant and utilization of 52.5% of the project cost and ensuring that SIA along with other stakeholders have already brought in their entire approved contribution in the Bank Account.

## 11. **Monitoring and Review**

- 11.1 The Governing Board of the SIA shall monitor at least once a quarter, the progress of the project and send a Quarterly Progress Report (QPR) to DIPP, on the prescribed proforma under the signature of the CEO of SIA.
- 11.2 An appropriate system of concurrent evaluation will be set up in the DIPP through outsourcing and/ or engaging a Project Monitoring Agency (PMA) to undertake field visits and build up a strong web enabled reporting mechanism, with documentary and visual inputs.
- 11.3 DIPP shall appoint its nominee to the Governing Body of the SIA.
- 11.4 The Apex Committee shall monitor the progress of the projects annually.

### 12. Project Management Agency

- 12.1 The DIPP would engage an independent agency called Project Management Agency (PMA) which will inter alia carry out both technical and financial appraisal of the project. PMA will appraise the DFR and DPR submitted by SIA, in particular with respect to the technical feasibility, financial inability and optimal utilization of the resources to be appended. The cost of engaging PMA shall be met from the funds earmarked separately for appraisal and monitoring of projects under administrative expenses.
- 12.2 The roles and responsibilities of PMA will be as follows:—
  - Evaluation of the proposals submitted by the SIA to the DIPP for the In-Principle Approval.
  - Evaluation of proposals for Final Approval.
- 12.3 PMA will not take up any consultation assignment with the project.

## 13 Project Management Consultant (PMC)

The SIA can engage a PMC depending upon its requirement; appointment of PMC would be optional for SIA and its necessity will differ from state to state.

### 14 Procurement of Goods and Services

- 14.1 All procurement of goods, equipment and services shall be done through an open, transparent and competitive process. Appropriate performance guarantee should be built in the agreement to ensure timely completion of the project.
- 14.2 Procurement policy must be as per Government's General Finance Rules (GFR).

#### 15. Assets

- 15.1 The Assets acquired/created by the SIA out of government assistance shall not be disposed, encumbered or utilized for the purposes other than for which the funds have been released.
- 15.2 A register of permanent and semi-permanent assets acquired wholly or mainly out of the funds provided by Government of India should be maintained in the Form GFR 19.
- 15.3 SIA will fix appropriate user charges for various facilities and services provided by it to fully recover O&M cost and make the project sustainable.
- 15.4 In case of dissolution of SIA or cancellation of the project at any point of time, all the assets and any unutilized grant shall vest with the Government of India.

### 16. Recall of the Central Grant

Apex Committee retains the right to curtail/recall the central grant along with applicable penal interest in case of unsatisfactory use of the grant including compromise with the quality envisaged, or partial/incomplete implementation of the project.

Annexure - A

### **COMPOSITION OF APEX COMMITTEE**

## <u>Chairman</u>

Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion

### **Members**

- 1. AS&FA in the Ministry of Commerce & Industry
- 2. Economic Adviser, DIPP
- 3. \*Representative, Planning Commission
- 4. \*Representative, Department of Science & Technology
- 5. \*Representative, Department of Commerce
- 6. \*Representative, Ministry of MSME
- 7. \*\*Secretary, Industries, from the concerned State Government
- 8. \*\*CEO of SIA and SPV/Industry Association
- 9. Representative from the concerned Financial Institution
- 10. GOI nominee in the Governing Body of the SIA

## **Member Secretary**

Joint Secretary, DIPP

Special Invitees: PMA PMCs

- \*Representatives shall not be below the rank of Joint Secretary.
- \*\*Secretary/CEO will attend in person. No representative shall be allowed to attend.